बिहार विशिष्ट मासिक करंट अफेयर्स- फरवरी 2021

बिहार के वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने FY22 के लिए बिहार सरकार 2,18,302.70 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है

- बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए 2,18,302.70 करोड़ रुपये का बिहार का पहला राजस्व-अधिशेष राज्य बजट पेश किया, जो वित्त वर्ष 2021 के अनुमानों (2,11,761.49 करोड़) की तुलना में 6,541.21 करोड़ रुपये जादा है।
- राज्य के राजकोषीय घाटे का अनुमान 22,510.78 करोड़ रुपये है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी-अनुमानित 7,57,026 करोड़ रुपये) का 2.97% है । बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3% की सीमा के भीतर रखने का प्रस्ताव किया गया है।
- कोई नया कर नहीं लगाया गया है, और बुनियादी ढांचे, सामाजिक क्षेत्रों और उद्यमिता के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- बिहार ने 2004-05 से लगातार राजस्व-अधिशेष राज्य होने का दावा किया है।

बिहार के राज्य प्रतीकों के बारे में तथ्य:

राज्य पक्षी: घरेलु गौरैया

राज्य पशु: गौर

राज्य फूल: कचनार

राज्य फल: आम

राज्य का पेड़: पीपल का पेड़

ओडिशा के 17 वें अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले में बिहार भागीदार राज्य

- ओडिशा ने भुवनेश्वर में 17वें मेगा व्यापार मेले की मेजबानी की है। अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले का उद्देश्य अचल संपत्ति के क्षेत्र में नवीनतम विकास को प्रदर्शित करना है।

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests

- 2021 मेले के लिए भागीदार देश बांग्लादेश है और इस वर्ष के लिए भागीदार राज्य बिहार है।
- फेयर का आयोजन उत्कल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (UCCI), बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और GS मार्केटिंग एसोसिएट्स के सहयोग से किया गया था।

न्यायमूर्ति एम रमण का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया

- बिहार और झारखंड राज्य के राज्यपाल रह चुके जस्टिस मंडगड़े राम जॉयस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
- उनका जन्म 27 जुलाई, 1931 को कर्नाटक में हुआ था।
- उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

बिहार कम कार्बन मार्ग के विकास के लिए UNEP के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है

- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2040 तक बिहार में जलवायु-लचीला और कम कार्बन विकास के लिए एक रोडमैप विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस समझौते पर बीएसपीसीबी के सदस्य सचिव अतुल बगई और यूएनईपी इंडिया के प्रमुख एस चंद्रशेखर ने हस्ताक्षर किए।
- समझौता ज्ञापन के तहत बिहार को UNEP से निम्नलिखित कार्यों में मदद मिलेगी:
- जलवायु प्रभाव भेद्यता आकलन विकसित करने के लिए
- जलवायु संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए बिहार की क्षमता में वृद्धि करने में
- एक ग्रीनहाउस गैस इन्वेंटरी (GHG) और कार्बन पदचिह्न विश्लेषण तैयार करने के लिए
- पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजनाओं (SAPCC) को संरेखित करने के लिए।

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests

बिहार बजट (2021-22) हाइलाइट्स

बिहार के वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के लिए बजट पेश किया था। 2021-22 की बजट राशि 2,18,303 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2020-21 के 6,542 करोड़ रुपये से अधिक) है, जो इसे बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बनाता है।

राज्य के लिए बजट का संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देना होगा।
- संविधान में "वार्षिक वित्तीय विवरण" के रूप में अभिहित किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का अनुमानित विवरण आमतौर पर "बजट" के रूप में जाना जाता है।

बजट में प्रयुक्त प्रमुख शब्द

राजस्व में शामिल हैं:

- राजस्व प्राप्ति
- राजस्व व्यय

राजस्व प्राप्ति:

- प्राप्तियां जो सरकार द्वारा पुनर्प्राप्त नहीं की जा सकती हैं।
- इसमें सरकार द्वारा करों और गैर-कर स्रोतों जैसे निवेश और ब्याज पर लाभांश के माध्यम से संकलित आय शामिल हैं।

राजस्व व्यय:

- ये भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च हैं।
- इसमें सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्यय शामिल हैं, राज्य सरकार को दिए गए अनुदान जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से उधार शामिल हैं।
- इसमें विदेशी सरकारों और विश्व संगठन से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान भी शामिल है।

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests

पूंजी जिसमें शामिल हैं

- पूंजीगत प्राप्ति
- पूंजीगत व्यय

पूंजीगत प्राप्ति: वे प्राप्तियां जो देयता उत्पन्न करती हैं या सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को घटाती हैं।

पूंजीगत व्यय

- यह सरकार द्वारा किया गया खर्च है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण होता है या केंद्र सरकार की वित्तीय देनदारियों में कमी आती है।
- इसमें भूमि, उपकरण खरीद, अवसंरचना निर्माण पर व्यय, शेयरों पर व्यय शामिल होगा।
- इसमें केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को गिरवी ऋण (mortgages) और केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज भुगतान आदि भी शामिल हैं।

प्रत्यक्ष कर: ये ऐसे कर हैं जो किसी व्यक्ति और कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं। इसमें शामिल हैं-

- आयकर
- निगम कर

अप्रत्यक्ष कर: ये ऐसे कर हैं जो माल एवं सेवाओं पर लगाए जाते हैं। इसमें निम्न कर शामिल हैं

- सेवा कर
- आबकारी कर
- सीमा शुल्क

राजकोषीय नीति: राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने और उसे प्रभावित करने के लिए अपने खर्च के स्तर और कर दरों को समायोजित करती है।

राजस्व घाटा: यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार का अतिरिक्त व्यय है।

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests

राजकोषीय घाटा: यह सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, जिसमें उधार शामिल नहीं है।

प्राथमिक घाटा: प्राथमिक घाटा वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को दर्शाता है।

गैर-कर राजस्व: ये सरकारी राजस्व हैं जो करों से उत्पन्न नहीं होते हैं।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP):

- यह एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश में तैयार सभी माल और सेवाओं का मूल्य है।
- यह एक देश की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करता है, इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।

बजट की मुख्य विशेषताएं:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

- FY22 के लिए राजकोषीय घाटा 22,510.78 करोड़ रुपये अनुमानित है। ।
- यह अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 2.97% है।
- वित्तीय वर्ष 2021 के बजट के आकार में 6,542 रुपये की वृद्धि हुई है।

व्यय

- 1,77,071.39 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के रूप में जबकि 41,231.31 करोड़ रुपये पूंजी खाता है।

कुल प्राप्तियां

- कुल प्राप्तियां 2,18,502.70 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जिसमें
    - राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से 1,86,267.29 करोड़ रुपये
    - 91,180.60 करोड़ रूपये केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी होगी।
    - पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 32,235.41 करोड़ रूपये।
    - सरकार के अपने कर राजस्व के लिए 35,050.00 करोड़ रूपये

राजस्व बचत

- यह 9,195.90 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

बजट 2021-2022 में नई योजना / नीति

- सात निश्चय योजना- इस योजना के तहत, राज्य सरकार सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार सृजन आदि पर जोर देगी।
    - आर्थिक हल, युवाओं को बल
    - आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार
    - हर घर नल का जल
    - घर तक पक्की गलियाँ, नालियाँ
    - शौचालय निर्माण- घर का सम्मान
    - अवसर बढ़े, आगे बढ़े
- निश्चय- 2 बिहार में सुशासन के तहत योजना- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट आवंटन 4671 करोड़ रुपये होगा। जिसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है-
    - युवा शक्ति, बिहार की प्रगति
    - सशक्त महिला, सक्षम महिला
    - हर खेत तक सिंचाई का पानी
    - स्वच्छ गाँव- समृद्ध गाँव
    - स्वच्छ शहर- विकसित शहर
    - सुलभ संपर्कता
    - सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा

क्षेत्र-वार व्यय

कृषि और संबद्ध गतिविधियां

- कृषि और संबद्ध गतिविधियों (2021-22 में): कृषि विकास के लिए कुल 3335.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य में हर खेत तक सिंचाई का पानी को लागू करने के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय का प्रस्तावित है।
- विद्युत विभाग के लिए 300 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- जल संसाधन विभाग के लिए 4074.38 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- 1561.72 करोड़ रुपये पशु और मत्स्य संसाधन के लिए आवंटित किए गए हैं।
- गंगा नदी के किनारे राज्य के 13 जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा।
- सहकारिता विभाग के लिए 1534.09 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- बाल हृदय योजना और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 300 करोड़।

शिक्षा

- बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों के साथ कौशल विकास और उद्यमिता विभाग की स्थापना के लिए 110 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।
- सभी आईटीआई में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- राजगीर में खेल विश्वविद्यालय के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की जाएगी।
- राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- महिला उच्च शिक्षा के लिए 600 करोड़ और महिला उद्यमिता के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

पर्यावरण क्षेत्र

- बिहार का दूसरा चिड़ियाघर 2021 तक अररिया में खोला जाएगा।
- इस क्षेत्र हेतु कुल बजट आवंटन- 737.75 करोड़।

विनिर्माण / औद्योगिक क्षेत्र

- कुल बजट आवंटन 1285.17 करोड़ रुपये जोकि विगत वर्ष से 40.33 करोड़ रूपये अधिक है।

ग्रामीण और शहरी विकास

- कुल बजट आवंटन- 16835.67 करोड़ रुपये
- राज्य भर के शहरों में ठोस कचरे के निपटान के 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम भी विकसित किया जाएगा।
- ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 250 करोड़।
- राज्य भर में बाईपास और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- सभी के लिए आवास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जैसी अन्य विभिन्न योजनाओं के लिए 7767.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    - नदी फ्रंट परियोजनाओं को पटना, बेगूसराय, छपरा, भागलपुर, आरा, बक्सर, हाजीपुर आदि में लागू किया जाएगा।

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests

- पटना मेट्रो रेल जिसकी कुल लंबाई 32.497 किलोमीटर है, को 2024 तक पूरा किया जाएगा और इसकी कुल लागत 11165.96 करोड़ रुपये हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

- सरकार ने लोक स्वास्थ्य सेवा हेतु 400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- राज्य में वरिष्ठ और बुजुर्ग लोगों के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग के लिए 90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- समाज कल्याण विभाग के लिए कुल बजट आवंटन- 8159.15 करोड़ रुपये है।
- पिछड़ा वर्ष और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए कुल बजट आवंटन- 1749.44 करोड़ रूपये।
- SC और ST कल्याण विभाग के लिए कुल बजट आवंटन- 1803.28 करोड़ रुपये।
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए कुल बजट आवंटन- 562.63 करोड़ रूपये

श्रम

- निश्चय -2 योजना के तहत 550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

संस्कृति

- बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसकी कुल लागत 145 करोड़ रुपये होगी।
- बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय पटना में स्थापित किया जाएगा।
- एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में स्थापित की जाएगी।

पंचायती राज

- राज्य भर में पंचायत संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- पंचायती राज विभाग के लिए 9544.93 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- लोहिया स्वच्छता योजना-2 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ।

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

1. बिहार बजट 2021-22 का आकार है

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests

उत्तर 2,18,303 करोड़ रुपये

2. बिहार के किस जिले में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी?

उत्तर पटना

3. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए बजट का आवंटन क्या है?

उत्तर 100 करोड़ रुपये

4. बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ खोला जाएगा?

उत्तर अररिया जिला

5. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए बजट आवंटन है-

उत्तर 30 करोड़

gradeup

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests